सोच और रिसर्च की जरूरत

सभी राजनीतिक दलों को समझना चाहिए कि वायरस के खिलाफ लड़ाई को किसी भी रूप में बाधित करना आत्मघाती होगा। खासकर मौजूदा दौर, जब दूसरी लहर उतार पर है और तीसरी लहर आने में थोड़ा वक्त है, हमारी तैयारियों के लिहाज से बेहद अहम है।

राम वर्मा।।

सरकार ने अपनी तरफ से यह स्पष्टीकरण देकर अच्छा किया है कि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन में नवजात बछड़ों का सीरम नहीं होता। सोशल मीडिया के जरिए फैली यह अफवाह महामारी की तीसरी लहर को रोकने के तमाम प्रयासों पर पानी फेर सकती है। हालांकि इसके मूल में आरटीआई के तहत पूछे गए सवाल से मिले जवाब को बताया जा रहा है, लेकिन इस जवाब को कांग्रेस के एक नेता ने जिस अंदाज में ट्वीट किया, उससे इस विवाद ने एक अलग ही रूप ले लिया। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद न केवल भारत बायोटेक और केंद्र सरकार की ओर से बल्कि ट्विटर पर सक्रिय जानकार लोगों की ओर से भी स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश हुई। इससे यह साफ हुआ कि मामला आरटीआई के तहत हासिल किए गए जवाब का उतना नहीं, जितना उसे समझने में हुई चूक का है। वेरो सेल विकसित करने के लिए अगर बछड़े के सीरम का इस्तेमाल होता है तो इसका मतलब यह नहीं हुआ कि फाइनल प्रॉडक्ट यानी वैक्सीन में भी यह सीरम होता है और न ही यह कि इसके लिए नवजात बछड़ों को मारा जाता है।

कोवैक्सीन पोलियो, रैबीज और इन्फ्लुएंजा के टीकों में भी इसका इस्तेमाल दुनिया भर में होता रहा है। मगर यहां मसला सिर्फ एक टेक्निकल मुद्दे को न समझने भर का नहीं, उसके राजनीतिक इस्तेमाल की मंशा का भी है। सेंट्रल ड्रग्स कंट्रोलर की ओर से मिले जवाब को ट्वीट करते हुए कांग्रेस नेता का यह कहना मायने रखता है कि मोदी सरकार ने कबूल किया है कि कोवैक्सीन में नवजात बछड़े का सीरम होता है... यह सूचना पहले ही सार्वजनिक की जानी चाहिए थी। जाहिर है, सरकार विरोधी तेवर के साथ ही इसमें धार्मिक भावनाओं को लाने की परोक्ष कोशिश भी है। ट्वीट के वायरल होने के पीछे इन दोनों कारकों की भी भूमिका रही है और इसी को रेखांकित करते हुए शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि जो वैज्ञानिक सोच और रिसर्च की जरूरत बताते रहते हैं, आज एक आरटीआई के आधार पर वैक्सीन में धार्मिकता के सवाल को लाकर लोगों में वैक्सीन संबंधी हिचक को बढ़ावा दे रहे हैं। अच्छी बात यह रही कि अपने एक नेता की ओर से किए गए इस ट्वीट को कांग्रेस ने भी ज्यादा तूल नहीं दिया। उसने खुद को इस विवाद से अलग रखा। सभी राजनीतिक दलों को समझना चाहिए कि वायरस के खिलाफ लड़ाई को किसी भी रूप में बाधित करना आत्मघाती होगा। खासकर मौजूदा दौर, जब दूसरी लहर उतार पर है और तीसरी लहर आने में थोड़ा वक्त है, हमारी तैयारियों के लिहाज से बेहद अहम है। इसी अंतराल में टीकाकरण की प्रक्रिया को तेज करके हम तीसरी लहर के रूप में आने वाली विपदा को टाल सकते हैं। ऐसे में सबकी कोशिश टीकाकरण प्रक्रिया को यथासंभव तेज करने की ही होनी चाहिए।

यज्ञादि की परिक्रमा

धर्म-दर्शन

अशोक वोहरा।

यह दीक्षा देने की परंपरा जैन धर्म में भी प्राचीनकाल से रही है, हालांकि दूसरे धर्मों में दीक्षा को अपने धर्म में धर्मांतरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाने लगा। धर्म से इस परंपरा को ईसाई धर्म ने अपनाया जिसे वे बपस्तिमा कहते हैं। अलग–अलग धर्मों में दीक्षा देने के भिन्न–भिन्न तरीके हैं। यहूदी धर्म में खतना करके दीक्षा दी जाती है।

प्रति गुरुवार को मंदिर जाना चाहिए। मंदिर में जाकर परिक्रमा करना चाहिए। भारत में मंदिरों, तीर्थों और यज्ञादि की परिक्रमा का प्रचलन प्राचीनकाल से ही रहा है। मंदिर की 7 बार (सप्तपदी) परिक्रमा करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह 7 परिक्रमा विवाह के समय अग्नि के समक्ष भी की जाती है। प्रदक्षिणा षोडशोपचार पूजा का एक अंग है। प्रदक्षिणा की प्रथा अतिप्राचीन है।

संपादकीय

गिरता ग्राफ

पिछले कुछ सालों से कांग्रेस के गिरते ग्राफ से हालात पार्टी के खिलाफ बने हैं। साथ ही कांग्रेस के अंदर नेतृत्वहीनता के कारण क्षेत्रीय दलों की उससे दूरी भी बढ़ी है। क्षेत्रीय दलों ने विपक्षी एकता न होने के लिए कांग्रेस को ही जिम्मेदार ठहराया। यह भी कहा गया कि जब राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष थे तब वह दूसरे दलों को जोड़ने में कामयाब नहीं रहे। पिछले कुछ दिनों से इसी धारणा को दूर करने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी ने संसद के मानसून सत्र में सभी दलों के साथ बेहतर समन्यव बनाने की पहल की। तमाम विपक्षी दलों के साथ होने वाली मीटिंग में राहुल गांधी सक्रियता से साथ निभा रहे हैं। वे अलग–थलग रहने वाले नेता की छवि को तोड़ना चाहते हैं। आगे यह कवायद किस दिशा में आगे बढ़ती है वह भी कई चीजें तय करेगी। उधर नवीन पटनायक की बीजेडी भी पिछले कुछ सालों में पहली बार कुछ–कुछ मसलों पर विपक्ष के साथ दिखने की कोशिश कर रही है। जाति जनगणना के मुद्दे पर वह विपक्षी दलों की मांग के साथ है। उधर के चंद्रशेखर राव की टीआरएस भी विपक्षी खेमे में अपनी जगह तलाश रही है। जानकारों के अनुसार जिस तरह बीजेपी ने इन दोनों राज्यों में पैठ बढ़ाई है उससे ये दोनों नेता चिंतित हैं। ये तमाम पहलू हैं जिनसे जुड़े सवाल विपक्षी एकता की दिशा और शर्तें तय करेंगे।

अब तक इन तमाम बैठकों से विपक्षी एकता को लेकर मिश्रित संकेत मिले हैं। लेकिन इतना तय है कि अगर विपक्षी एकता को आकार लेना है तो इन नेताओं को कई सवालों के जवाब तलाशने होंगे जो उठने शुरू हो गए हैं।

मुद्दों पर बनानी होगी सहमति

नरेन्द्र नाथ।।

पिछले कुछ दिनों से 2024 आम चुनावों के मद्देनजर विपक्षी एकता की कोशिशें तेज हो गई हैं। हर कोई अपने स्तर पर इसे आकार देने के लिए सक्रिय है। कभी ममता बनर्जी तो कभी शरद पवार, कभी राहुल गांधी तो कभी सोनिया गांधी– सभी इसमें भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं। अब तक इन तमाम बैठकों से विपक्षी एकता को लेकर मिश्रित संकेत मिले हैं। लेकिन इतना तय है कि अगर विपक्षी एकता को आकार लेना है तो इन नेताओं को कई सवालों के जवाब तलाशने होंगे जो उठने शुरू हो गए हैं।

कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के साथ ही अधिकतर क्षेत्रीय दलों के नेताओं ने 2004 मॉडल को फिर से अपनाने की मंशा दिखाई है। 2004 में यूपीए के गठन के पीछे भी सोनिया गांधी की पहल थी। तमाम क्षेत्रीय दलों को एक मंच पर लाने के बाद ही अटल बिहार वाजपेयी की अगुआई वाली एनडीए सरकार को 2004 में अप्रत्याशित रूप से हटाने में कामयाबी मिली। तब आम सहमति से तय हुआ था कि नेता का मसला चुनाव के बाद देखा जाएगा। ऐसा ही कुछ इस बार करने की तैयारी दिख रही है। 20 अगस्त को हुई विपक्षी दलों की बड़ी मीटिंग में भी अधिकतर नेताओं ने इसी पैटर्न की बात कही। लेकिन इस बार मामला उतना आसान

नहीं है। 2004 के मुकाबले 2024 में बड़ा बदलाव आ चुका है। हाल के समय में चुनाव नाम के दम पर लड़ने का ट्रेंड बढ़ा है। आम चुनाव में मोदी बनाम कौन का सवाल उठ सकता है। यह मुद्दा 20 अगस्त की मीटिंग में भी उठा। महाराष्ट्र के सीएम और शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने कहा कि भले नेता का चुनाव बाद में तय करने का फैसला ले लिया जाए लेकिन फिर भी यह बात जेहन में रखनी होगी कि जब हम जनता के बीच जाएंगे तो लोग यह सवाल पूछ सकते हैं। हालांकि ममता बनर्जी ने कहा कि मोदी के सामने हम जनता को चेहरा बनाएंगे। आम राय बनी कि अभी विपक्षी एकता की कोशिश को आगे बढ़ाया जाए और नेतृत्व के सवाल को आगे के लिए छोड़ दिया जाए।

नेतृत्व के अलावा दूसरा अहम मसला जो मीटिंग में उठा वह था मुद्दों का। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने मीटिंग में इस बात पर चिंता जताई कि विपक्ष का अधिकतर समय ऐसे मुद्दों में चला जाता है जिससे आम लोगों का सरोकार नहीं होता। परोक्ष रूप से उन्होंने पेगासस जासूसी कांड की ओर इशारा किया। उनका कहना था इससे बड़ा मसला महंगाई या बेरोजगारी है। उनकी बातों का कुछ अन्य दलों ने समर्थन किया। वहीं तेजस्वी यादव ने परोक्ष रूप से कांग्रेस से कह दिया कि वह क्षेत्रीय दलों को अधिक जगह दे। उनका इशारा कांग्रेस की ओर से चुनावों में अधिक सीट मांगने के लिए दबाव देने की ओर था। भले विपक्षी एकता के लिए होम वर्क अभी से शुरू हो गया हो, लेकिन अभी अधिकतर दल खासकर क्षेत्रीय पार्टियां उसे अंतिम रूप देने के मूड में नहीं हैं। वे इसके लिए अगले साल तक इंतजार करना चाहेंगी।

दरअसल 2022 में कई ऐसी सियासी घटनाएं होंगी जो इन प्रयासों को नया आकार दे सकती हैं। विपक्ष को सबसे पहले उत्तर प्रदेश विस चुनाव की बाधाा पार करनी है। जीत–हार के अलावा विपक्षी दलों को लगता है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीजेपी की सीटें कम हुईं तो 2022 का राष्ट्रपति चुनाव दिलचस्प हो सकता है। इसके अलावा 2024 से पहले गुजरात, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं।

सूडोकु नवताल-5266

सरल

7	8	6		1		5		2
	9			8				3
1			6	9		7		
	3	8	2		1			
2	7	5				6	3	1
			5		7	2	8	
		9		7	4			6
8				2			5	
4		2		5		9	1	7

- प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं.
- प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें.
- पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते.
- पहेली का केवल एक ही हल है.

सूडोकु नवताल -5265 का हल

2	9	5	3	1	4	6	8	7
3	6	1	2	8	7	4	9	5
8	4	7	5	9	6	3	2	1
5	7	4	1	6	2	8	3	9
1	3	6	9	4	8	5	7	2
9	8	2	7	3	5	1	4	6
6	2	8	4	7	1	9	5	3
4	5	3	6	2	9	7	1	8
7	1	9	8	5	3	2	6	4

अपना ब्लॉग

नियोजनयोग्य बनाने में मदद

मोहन। अब तक 2461 कार्य भूमिकाओं के लिए 13 हजार से अधिक मानक पाठ्यक्रम तैयार किए जा चुके हैं। सही मायने में यह उपलब्धि 6.5 लाख युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। उससे भी बड़ी बात यह है कि ये सभी पाठ्यक्रम उद्योग–व्यवसाय जगत की जरूरतों को देखते हुए उनके साथ मिलकर तैयार किए गए हैं। इससे प्रशिक्षण को उद्योगसम्मत तथा प्रशिक्षार्थियों को नियोजनयोग्य बनाने में मदद मिली है और इसका लाभ आगामी वर्षो में स्पष्ट दिखाई देगा।

हम कह सकते हैं कि कौशल विकास के लिए जिस संरचना की जरूरत है, उसका विकास हो चुका है। ऊर्जावान युवाओं की बड़ी संख्या भी मौजूद है। बस कौशल क्षेत्र को सामाजिक प्रतिष्ठा दिलाने की चुनौती है। जिस दिन इस मोर्चे पर हमने उपयुक्त तैयारी कर ली, भारत को विश्व की कौशल राजधानी बनने से कोई रोक नहीं सकेगा।